International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 03, No. 03(I), July - September, 2021, pp.181-184

भारत में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों की समस्याओं और संभावनाओं का एक अध्ययन

लखन लाल चौकसे*

सार

प्रस्तुत शोध पत्र में भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की समस्याओं और संभवानाओं पर प्रकाश डाला गया है, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग को भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे देश के समग्र औद्योगिक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण योगदान देकर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में महत्ती भूमिका निभा रहे हैं। यह लगभग 12 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। स्व–रोजगार एवं अन्य रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में यह क्षेत्र कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाता है व राष्ट्रीय आय में वृद्धि और धन का समान वितरण सुनिश्चित करने व क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने, जिससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक में मदद करता है और विनिर्माण उत्पादन के 45 प्रतिशत के साथ–साथ देश के निर्यात का 40 प्रतिशत एमएसएमई क्षेत्र में होता है। वर्तमान में देश की जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 29 प्रतिशत है, इसके अतिरिक्त एमएसएमई के श्रमिक–पूँजी अनुपात भी अत्यधिक है।

शब्दकोशः *एमएसएमई परिभाषा, भूमिका और प्रदर्शन, सरकारी नीतियाँ और समस्याऐं।*

प्रस्तावना

सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को विश्व भर में विकास के इंजन के रूप में जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह उद्यम अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि हमारे देश में समग्र औद्योगिक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण योगदान देकर रोजगार सृजन का बढ़ावा देने में महत्ती भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में कार्यरत 7 करोड़ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग देश में लगभग 12 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर विभिन्न क्षेत्रों में सृजित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एमएसएमई के लिये श्रमिक–पूँजी अनुपात भी अत्यधिक है। एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल में भारत सरकार ने सूक्ष्म,लघु और मध्यम विकास अधिनियम 2006 विनियमित किया है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम के संवर्धन एवं विकास का सरल व सुविधाजनक बनाना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। 2 अक्टूबर 2006 से लागू इस अधिनियम ने इस क्षेत्र को दीर्घावधि मांग को पूरा कर दिया।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में पिछले पाँच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बेहद जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। एमएसएमई बड़ें उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूँजी लागत में बड़े रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं व राष्ट्रीय आय और धन की अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने, जिससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण में मदद करते हैं। एमएसएमई के सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरण है और यह क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिये काफी योगदान देता है। 2019 में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार, एमएसएमई पिछले 4 वर्षों में सबसे बड़ा रोजगार–उत्पादक रहा है, विशेष रूप से आतिथ्य और पर्यटन, वस्त्र और परिधान, धातु, उत्पाद, मशीन कलपुर्जों और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में।

---

[6] शोधार्थी वाणिज्य विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्यप्रदेश।

अध्ययन का उद्देश्य

- निवेश सीमा के आधार पर एमएसएमई की परिभाषा को समझना।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका और प्रदर्शन को समझना।
- भारत में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिये सरकारी योजनाओं को समझना।
- भारत में एमएसएमई की समस्याओं को समझना।

शोध प्रविधि एवं समंको का संकलन

यह अध्ययन द्वितीय समंकों पर आधारित है। द्वितीय समंक प्रकाशित पुस्तकों, जर्नल एवं इंटरनेट के माध्यम से संकलित किये गये हैं।

एमएसएमई की परिभाषा

श्रेणी	विनिर्माण (रूपये में) (संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश)	सेवाएं (रूपये में) (उपकरण में निवेश)
सूक्ष्म	25 लाख से अधिक नहीं	10 लाख से अधिक नहीं
लघु	25 लाख से अधिक किन्तु 5 करोड़ से कम	10 लाख से अधिक किन्तु 2 करोड़ से कम
मध्यम	5 करोड़ से अधिक किन्तु 10 करोड़ से कम	2 करोड़ से अधिक किन्तु 5 करोड़ से कम

एमएसएमई की भूमिका

- **रोजगारः** यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है। यह भारत में लगभग 120 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है।
- **सकल घरेलू उत्पाद में योगदानः** देश के भौगोलिक विस्तार में लगभग 36.1 मिलियन इकाइयों के साथ, एमएसएमई विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 6.11 प्रतिशत और सेवा गतिविधियों से सकल घरेलू उत्पाद का 24.63 प्रतिशत योगदान करते हैं।

एमएसएमई मंत्रालय ने 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में अपने योगदान को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गया है।

- **निर्यातः** यह भारत से कुल निर्यात में लगभग 45 प्रतिशत का योगदान देता है।
- **समावेशी विकासः** एमएसएमई ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं।
- **वित्तीय समावेशनः** टियर–II और टियर – III शहरों में छोटे उद्योग और खुदरा व्यवसाय लोगों के लिये बैंकिंग सेवाओं और उत्पादों का उपयोग करने के अवसर पैदा करते हैं।
- **नवाचार को बढ़ावाः** यह नवोदित उद्यमियों को रचनात्मक उत्पादों का निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है जो व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं और विकास को बढ़ावा देते हैं।

इस प्रकार भारतीय एमएसएमई क्षेत्र राष्ट्रीय आर्थिक संरचना की रीढ़ है और वैश्विक आर्थिक झटकों और प्रतिकूलताओं को दूर करने के लिये लचीलापन प्रदान करते हुये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये एक कवच के रूप में कार्य करता है।

एमएसएमई को बढावा देने के लिये सरकारी योजनाऐं

- **उद्यमी मित्र पोर्टलः–** सिडबी द्वारा एमएसएमई को क्रेडिट और हैंडहोल्डिंग सेवाओं की पहुँच में सुधार के लिये लॉन्च किया गया।
- **एमएसएमई संबंधः–** केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसएमई से सार्वजनिक खरीद के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

- एमएसएमई समाधान–एमएसएमई विलंबित भुगतान पोर्टल देश भर के सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई/ राज्य सरकारों द्वारा विलंबित भुगतान से संबंधित अपने मामलों को सीधे दर्ज करने के लिये सशक्त करेगा।
- **डिजिटल एमएसएमई योजनाः–**इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग शामिल है जहाँ एमएसएमई इंटरनेट का उपयोग आम और साथ ही दर्ज आईटी बुनियादी ढांचे तक पहुँचना के लिये करते हैं।
- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रमः–** यह एमएसएमई मंत्रालय के तहत एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है।
- **पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिये निधि की संसोधित योजना (SFURTI) :–** पारंपरिक उद्योगों ओर कारीगरों को समूहों मे संगठित करना और उनकी विपणन क्षमता को बढ़ाकर और उन्हें बेहतर कौशल से लैस करके उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाना।
- **नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये एक योजना (एस्पायर):–** नई नौकरियाँ पैदा करती है और बेरोजगारी को कम करती है, उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देती है, अभिनव व्यापार समाधान आदि की सुविधा प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम (एनएमसीपी):–** भारतीय एमएसएमई के बीच उनकी प्रक्रियाओं, डिजाइन, प्रौद्योगिकी और बाजार पहुँच में सुधार करके वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक विकसित करना।
- **सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रमः–** एमएसएमई की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साथ–साथ क्षमता निर्माण के लिये क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को अपनाता है।

एमएसएमई के लिये प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिये क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) चालू है।

इसलिए सरकार को मानव क्षमता विकास, ज्ञान सेवाओं वित्त तक पहुँच, प्रौद्यागिकी, बुनियादी ढांचे, बाचार पहुँच और व्यापार करने में आसानी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एमएसएमई के समग्र विकास के लिये ठोस प्रयास करना जारी रखना चाहिये।

भारत में एमएसएमई की मुख्य समस्याऐं

- बैंक वित्त की कमी और समय पर आपूर्ति का अभाव।
- सीमित पूँजी और ज्ञान।
- शक्ति की कमी।
- कम गुणवत्ता वाले इनपुट।
- कम रिटर्न।
- तकनीकी की अनुपलब्धता।
- कम उत्पादन क्षमता।
- अप्रभावी विपणन रणनीतियां।
- नये बाजारों की पहचान।
- आधुनिकीकरण और विस्तार में बाधाऐं।
- परिवहन समस्याऐं।
- जानकारी का अभाव।
- प्रशिक्षण की कमी।
- उच्च प्रतिस्पर्धा।
- वहनीय लागत पर अत्यधिक कुशल श्रम की अनुपलब्धता।

निष्कर्ष

संक्षेप में, एमएसएमई क्षेत्र में भारत की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुये रोजगार सृजन, निर्धनता, निवारण क्षेत्रीय विकास, नवोन्मेष इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है यह बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूँजी लागत में बड़े रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एमएसएमई के विकास के लिये दिन–प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएँ व प्रयास किये जा रहे हैं फिर भी इन उद्यमों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि एमएसएमई अपनी विषम परिस्थितियों से निपटकर सकरात्मक दिशा में कार्य करे तो रोजगार सृजन के साथ–साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. योजना (मासिका पत्रिका) सितम्बर 2018, पृष्ठ संख्या 52,53,57 व 58
2. कुरूक्षेत्र (मासिक पत्रिका) अप्रैल 2020, पृष्ठ संख्या–10
3. क्रॉनिकल (मासिक पत्रिका) सितम्बर 2020, पृष्ठ संख्या 12 व 47
4. https://www.abplive.com/business/msme
5. https://m.economictimes.com/hindi/news/
6. https://www.smechamberofindia.com
7. https://www.indiabudget.nic.in
8. https://www.rbi.org.
9. https://www.msme.gov.in
10. https://www.eria.org
11. https://www.disr.gov.in

❖◆❖